Dr.Raman Kumar Thakur
Assistant professor (Guest)
Department of Economics,
D.B.College, Jaynagar,Madhubani.
L.N.M.U.DARBHANGA.

Class:-B.A.Part-2 (Hons)
Paper -4.

18 May 2020

TOPIC:- भारत में आर्थिक सुधार- उदारीकरण, निजीकरण व विश्वव्यापीकरण
(ECONOMIC REFORMS IN INDIA- LIBERALISATION, PRIVATISATION AND GLOBALISATION)

→ नई आर्थिक नीति से अभिप्राय जुलाई 1991 के बाद से किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों और परिवर्तनों से है जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की परिधि में लाकर उसे प्रतियोगी बनाकर उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि करना है.
प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान-प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण तभी संभव है जब ऐसे आदान-प्रदान के मार्ग में किसी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाए और इन्हें कोई ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था संचालित करें जिसमें सभी देशों का विश्वास हो और जो सर्वानुमति से नीति-निर्धारक सिद्धांतों का निरूपण करें।समान नियम के अनुसार में रहकर जब सभी देश अपने व्यापार और निवेश का संचालन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह एक ही धारा प्रवाहित होते हैं, यही वैश्वीकरण है. भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियों में एक नीति अर्थव्यवस्था के ' वैश्वीकरण (Globalisation) की है इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुराब करना है. इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात की खुली छूट सीमा शुल्क में कमी विदेशी पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी के निवेश की छूट तथा रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय करना इत्यादि उपायों का समावेश किया गया है. यह उपाय एक बार में ही लागू किए जाने वाले उपाय नहीं है बल्कि इन्हें विभिन्न चरणों में लागू किया जाना चाहिए ।

* नई आर्थिक नीति के मुख्य अंग है जिसे इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है:-

1). नई औद्योगिक नीति (New industrial policy) →नई औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत बहुआयामी औद्योगिक नीति सुधारो द्वारा भारतीय उद्योग में संरक्षणवाद को समाप्त करके प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का सूत्रपात किया गया , सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विनियोग के लिए सुरक्षित क्षेत्रों को 18 से कम करके अब केवल तीन कर दिया गया है. केवल 6 उद्योगों को छोड़कर सभी प्रकार की औद्योगिक

इकाइयों को लाइसेंस लेने से मुक्त कर दिया गया है. साथ ही एम.आर.टी.पी. की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है तथा विदेशी पूंजी विनियोग की सीमा को बढ़ाकर विदेशी पूंजी को आकर्षित किया गया है।

2). नई राजकोषीय नीति(New fiscal policy):- भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का एक प्रमुख लाश राजकोषीय घाटा यूपी 1990 कान में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 8.5% को कम करके 4% करना है इसके लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करो में बुरे भी सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश व सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन कीमतों में वृद्धि करना है.

3). नई निवेश नीति(New Investment policy):- 1991 की आर्थिक नीति के अंतर्गत विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण किया गया है जिसमें 'फेरा' को बदलकर 'फेमा' किया गया है।

4). नई व्यापार नीति(New Trade policy):- नई आर्थिक नीति में अर्थव्यवस्था के खुलेपन के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए सीमा शुल्क तथा टैरिफो को धीरे-धीरे कम किया गया. अर्थव्यवस्था के खुलेपन का विस्तार करने के लिए विदेशी निवेश तथा आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहित किया गया है। विनिमय दर का समायोजन करने के लिए सरकार ने जुलाई 1991 में रुपए का औसतन 18.5% अवमूल्यन कर दिया है. इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन ,आयात प्रतिस्थापन तथा पूंजी की अन्तरवाह की गति को तीव्र करना था. निर्यातो को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रुपए को व्यापार खाते में 1993 -94 से पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है।

4). नई मौद्रिक नीति(New Monetary policy):- सरकार ने मौद्रिक सुधार के लिए 'नरसिम्हन कमेटी' की नियुक्ति की थी इस कमेटी की मुख्य सिफारिशों के आधार पर बैंकों को ब्याज दरों के स्वतंत्र निर्धारण का अधिकार दिया गया बैंकों को अधिक स्वतंत्रता देते हुए बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना की गई है।